

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
पीठासन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :- 355/22

प्रार्थी :-

नारायण पुत्र कालू, जाति भील, निवासी ग्राम मंडापुरा,
तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर, राजस्थान।

बनाम

विप्रार्थी :- जिला ओद्योगिक अधिकारी, बालोतरा, खेड रोड, बालोतरा
तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी.ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट



उपस्थित :- 1. श्री करणसिंह वकील प्रार्थी अधिवक्ता
2. विप्रार्थी :- अनुपस्थित

आदेश _____ दिनांक :- 23.5.2023

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 367 क्षेत्रफल 1.7705 हैक्टेयर ग्राम मंडापुरा, तहसील पचपदरा में अवस्थित है। उक्त खेत व सड़क के मध्य विप्रार्थी का भूमि खसरा संख्या 1164/359 क्षेत्रफल 3.4145 हैक्टेयर भूमि आई हुए है।

प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थी की उक्त खसरे में से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरता पड़ता है। लेकिन रिकॉर्ड में कटाण नहीं होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है, जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है, और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है, क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 367 क्षेत्रफल 1.7705 हैक्टेयर ग्राम मंडापुरा, भूमि में से होकर गुजरते

हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि नक्शा परिशिष्ट "अ" में दर्शाये मार्क ए

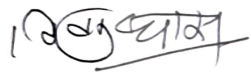
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

से है एक बरसा लाल के रास्ता चौड़ा 30 फीट का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी रास्ते में गैर भूमिकेन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

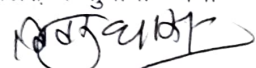
प्राथीनता का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्राथीनता को जरिये रजिस्ट्रार नोटिस तलब किया गया व तहसीलदार पंचपदरा से मौका रिपोर्ट तलब की गयी। विप्राथी द्वारा जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्राथी ने उद्योग विभाग के खसरा नं. 144, 258 मौजा मंडापुरा तहसील पंचपदरा में से 30 फिट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। मंडापुरा में खातेदारी की उक्त भूमि मूल्यवान सरकारी भूमि है, उक्त भूमि पर अति निकट भविष्य में इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो की स्थापना करने की माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2023 - 24 में है अतः यहां से रास्ता देना उचित नहीं होगा, साथ ही इस भूमि के आवेदन हेतु प्रस्ताव सरकार के पास विचारधीन है।

हमने पत्रावली व प्रत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन अध्ययन किया गया। प्राथी द्वारा प्रस्तुत जबाब का अवलोकन किया, बाद गौर प्राथी द्वारा चाहा गया रास्ता राज्य हित में सरकारी विभाग हेतु प्रस्तावित होने के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर निरस्त कर खारिज किया जाता है। प्राथी अलग से अन्य स्थान से रास्ता मांगने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र होगा।




(विवेक व्यास)
उप-सहायक अधिकारी
(सि.डी.ओ.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 23.05.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया


उप-सहायक अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा